

अब्दुल्ला मोहम्मद पगारकर

बनाम

राज्य (केंद्र शासित प्रदेश गोवा,दमण और दीव)

11 सितंबर, 1979

[सैयद मुर्तजा, फैजल अली एडी कोशल]

अधिनियम: आपराधिक मुकदमा - लोक सेवक पर गलत मस्टर रोल तैयार करने, वेतन और अन्य बिलों को बढ़ाने का आरोप लगाया गया सबूत का बोझ किस पर है।

भारतीय दंड संहिता.एस.एस. 120(बी)(1), 420, 468 और 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एस.5(1) (डी)- के तहत दोषसिद्धि - की वैधता।

पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दो नदियों को जोड़ने वाली नहर को मानसून के मौसम के दौरान जहाजों के लिए नौगम्य बनाने के लिए तत्काल गहरीकरण और चौड़ीकरण की आवश्यकता होती है जब समुद्र उग्र हो जाता है और नदी के मुहाने पर नेविगेशन खतरनाक हो जाता है। अपीलकर्ता (ए-1) जो उस समय बंदरगाहों का कप्तान था, ने प्रेस विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कीं और दूसरी अपील (ए-2) में अपीलकर्ता एकमात्र व्यक्ति था जिसने निविदा प्रस्तुत की थी। चूंकि टेंडर ही प्राप्त हुआ था, इसलिए उपराज्यपाल ने इसे

मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया। उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि तात्कालिकता को देखते हुए मंजूरी की प्रत्याशा में काम तुरंत शुरू किया जा सकता है। फिर भी ए-1 ने काम ए-2 को सौंप दिया जिसने काम शुरू कर दिया। इसी बीच भारत सरकार ने निर्देश दिया कि कार्य विभागीय स्तर से कराया जाये. ए-1 ने श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिए लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली यह थी कि ए-2 ने वास्तव में प्रत्येक दिन किए गए कार्य पर अपने हस्ताक्षर के बिना हाथ से लिखे बयान प्रस्तुत किए, जिसमें खुदाई की गई मिट्टी और नमक के घन मीटर की मात्रा, संख्या (बिना नाम के) निर्दिष्ट की गई थी। नियोजित पुरुष और महिला श्रमिकों की संख्या, अनुमोदित दरों पर श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी इत्यादि। ए-1 ने आवश्यक विवरण अपने कार्यालय में टाइप करवाए और उन्हें संबंधित विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा । इसके बाद ए-1 ने रकम निकाली और नियमित रसीद के बदले ए-2 को नकद भुगतान किया।

इस दौरान लेखा निदेशालय ने काम में लगे मजदूरों का मस्टर रोल मांगा। ए-1 ने एक रजिस्टर और मस्टर रोल तैयार किया। मस्टर रोल की वास्तविकता के बारे में संदेह होने पर, मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया, जिसने बताया कि कुल राशि रु 76,247/43 सरकार द्वारा ए-1 को

4.73 लाख रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन किया गया कार्य रुपये से अधिक का नहीं था।

विशेष न्यायाधीश ने दोनों अपीलकर्ताओं को इस आधार पर दोषी ठहराया और सजा सुनाई कि उन्होंने काम के निष्पादन के मामले में बढ़े हुए बिल पेश करके और वास्तव में खर्च की तुलना में कहीं अधिक राशि प्राप्त करके सरकार को धोखा देने की साजिश रची थी और प्रस्तुत मस्टर रोल झूठे दस्तावेज थे। न्यायिक आयुक्त ने विशेष न्यायाधीश के निष्कर्षों को बरकरार रखा।

अपीलों को स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित किया: 1. रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि ए-2 द्वारा प्रस्तुत निविदा वास्तव में सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी और उसी आधार पर पूरा काम निष्पादित किया गया था। [612 बी]

2. हालांकि यह कहना सही हो सकता है कि विभागीय तौर पर किया जाने वाला काम भी किसी ठेकेदार को सौंपा जा सकता है, लेकिन मौजूदा मामले में कोई बिल नहीं निकाला गया और न ही किसी भुगतान को मंजूरी दी गई। ठेकेदार के रूप में काम कर रहे ए-2 के माध्यम से कार्य के किसी भी हिस्से को निष्पादित करने का आधार । बिल में नियोजित मजदूरों की संख्या और स्वीकृत दरों पर उनकी मजदूरी से संबंधित राशि शामिल थी। बिलों में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि काम किसी

ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है. ए -2 ने किसी भी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए और उसका नाम तथा कार्य के निष्पादन के साथ उसका संबंध उसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट रहा। [612 सीई]

3. आरोप के प्रत्येक घटक के अस्तित्व को साबित करने का दायित्व हमेशा अभियोजन पक्ष पर रहता है और कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है। यह राज्य पर सभी उचित संदेहों से परे लाने के लिए बाध्य था कि काम को पूरा करने में वास्तव में नियोजित श्रमिकों की संख्या सरकार द्वारा भुगतान किए गए बिलों के साथ संलग्न सारांश में बताई गई संख्या से कम थी। [614 डीई]

4. यद्यपि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बताई गई प्रत्येक दिन काम पर लगाए गए मजदूरों की संख्या और बिलों में दर्शाई गई संख्या के बीच अंतर था, लेकिन ऐसा नहीं है कार्य निष्पादित होने के लंबे समय बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों की छाप पर भरोसा करना सुरक्षित है । [614 एफ]

5. कार्य के निष्पादन में अपीलकर्ता द्वारा की गई अनियमितताएं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती हैं जो कार्य के निष्पादन के संबंध में अपीलकर्ताओं की प्रामाणिकता के संबंध में एक मजबूत संदेह को जन्म देती है, लेकिन केवल संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, प्रमाण का

विकल्प नहीं हो सकता। आपराधिक आरोप के आरोपी व्यक्ति पर बेगुनाही साबित करने का बोझ डालना संभव नहीं है [614 एच]

6. वास्तव में किए गए काम के मूल्य के संबंध में नीचे की अदालतों द्वारा निकाले गए आंकड़ों में भारी असमानता थी। नीचे दिए गए न्यायालयों का विचार है कि यह अभियुक्त को दिखाना था कि नियोजित श्रमिकों की संख्या बिलों से जुड़े सारांशों में प्रत्येक दिन दिखाई गई संख्या के अनुरूप है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे कानून द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। [616 एच-617 ए]

7. अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं किया है कि बिल या सारांश भौतिक विवरणों में झूठे थे। यद्यपि अपीलकर्ताओं ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों के निष्पादन के मामले में संबंधित नियमों और सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के प्रक्रियात्मक व्यवहार के सामान्य मानदंडों की घोर अवहेलना करते हुए कार्य को निष्पादित किया, लेकिन इस तरह की उपेक्षा किसी भी मामले में नहीं की गई है। जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है। निचली अदालतों के निष्कर्ष निस्संदेह संदेह को और भी मजबूत बनाते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप की कोई भी सामग्री तैयार की गई थी। [618 सी, ईएफ]

8. हालाँकि कुछ दस्तावेज़ अपीलकर्ताओं के कहने पर तैयार किए गए थे जब लेखा विभाग द्वारा उनकी मांग की गई थी, लेकिन इसके

किसी भी प्रमुख के संबंध में आरोप को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, उनका कोई सबूत नहीं है उन दस्तावेजों में की गई किसी भी प्रविष्टि के मिथ्या होने का । [618 एच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 224 और 268/1977

न्यायिक आयुक्त न्यायालय के 1973 की आपराधिक अपील संख्या 19 और 21 में पणजी में गोवा, दमन और दीव में निर्णय एवं आदेश दिनांक 19-3-77 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

सीआरएल ए. क्रमांक 224/77 में अपीलकर्ता के लिए टी. गोदीवाला, पीसी घोखले और बीआर अग्रवाल।

सीआरएल ए. क्रमांक 268/77 में अपीलकर्ता के लिए एस. भंडारे। प्रतिवादी की ओर से एचआर खन्ना और एमएन श्रॉफ।

न्यायालय का निर्णय कोशल, जे द्वारा सुनाया गया। इस निर्णय के द्वारा हम 1977 की आपराधिक अपील संख्या 224 और 268 का निपटान करेंगे, जिनमें से दोनों में न्यायिक आयुक्त, गोवा के 19 मार्च, 1977 के निर्णय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। अपीलकर्ताओं और ट्रायल कोर्ट द्वारा उन पर लगाई गई सजा को चुनौती दी गई है।

अपीलकर्ताओं पर विशेष न्यायाधीश, पणजी द्वारा संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिन्होंने उन्हें दोषी पाया और उन्हें नीचे दी गई तालिका के अनुसार दंड दिया:

क्रम	नाम अभियुक्त	विधि की धारा जिस पर दोष सिद्ध होने पर अभियोग दर्ज किया गया	सजा
1	2	3	4
1	अब्दुल्ला मोहम्मद	(ए) धारा 120 बी(1) के साथ धारा 420, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता, धारा 5 (1) डी भ्रष्टाचार अधिनियम (बी) धारा 420 और 468 और धारा 109 पढ़ा	कठोर कारावास 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना के साथ एक महीने के लिए कठोर कारावास की सजा कठोर कारावास- दो साल के लिए के

		<p>और धारा 468 और 471 भारतीय दंड संहिता</p>	<p>साथ जुर्माना रु 500/-, एक महीने की कठोर कारावास</p>
		<p>सी) धारा 5(2) धारा 5(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम</p>	<p>कठोर कारावास- दो साल की सजा, दो लाख रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर अठारह महीने की कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी</p>
		<p>(ए) धारा 120 बी(1) धारा</p>	<p>कठोर कारावास- दो साल और रुपये 500/- का</p>

2	मोresh्वर हरि महात्मे	420, 468, 471 भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के साथ पठित, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी), (बी) भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के साथ पठित, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की	जुर्माना लगाया जुर्माना अदा न करने पर एक माह के कठोर कारावास की सजा होगी कठोर कारावास-
---	--------------------------	--	--

		<p>धारा 5(1)(डी),</p> <p>(ग) धारा 420, 468 और 471, धारा 109 भारतीय दंड संहिता</p>	<p>दो साल और रुपये 500/- का जुर्माना लगाया जुर्माना अदा न करने पर एक माह के कठोर कारावास की सजा होगी</p> <p>कठोर कारावास- दो साल की सजा, दो लाख रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर अठारह महीने की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी</p>
		<p>(डी) धारा 5(2) धारा 5(1)घ</p>	

		भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 109 भारतीय दंड संहिता	
--	--	--	--

प्रत्येक अभियुक्त के मामले में कारावास की सभी मूल सजाएँ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया। यहां यह कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 477ए के तहत लगाए गए आरोप साबित नहीं पाए गए और उन्हें बरी कर दिया गया।

2. अभियोजन मामले को कुछ लंबाई में निर्धारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार कहा जा सकता है। वर्ष 1965 में अपीलकर्ता अब्दुल्ला मोहम्मद पगारकर (बाद में ए-1 के रूप में संदर्भित) सर्वेयर-इन-चार्ज, मर्केटाइल मरीन डिपार्टमेंट, मार्मागोआ के साथ-साथ कैप्टन ऑफ पोर्ट्स, पणजी का पद भी संभाल रहे थे। उनकी अंतिम क्षमता में, कुम्बरजुआ नहर को गहरा और चौड़ा करने का काम, जो जुआरी नदी को मंडोवी नदी से जोड़ता है, उनके लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी क्योंकि मानसून के मौसम के दौरान खदानों के उपयोग के लिए नहर को कम ज्वार पर नौगम्य बनाया जाना था जब समुद्र यह उबड़-खाबड़ हो

जाता है और अगुडा में मांडोवी नदी के मुहाने को पार करना खतरनाक हो जाता है। मारमार्गोआ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नहर का सर्वेक्षण किया गया था और इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई थी। ए-1 द्वारा प्रेस में एक विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और अपीलकर्ता मोरेश्वर हरि महात्मे (इसके बाद ए-2 के रूप में वर्णित) इसे प्रस्तुत करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, जिसे उन्होंने 5 जनवरी, 1966 को प्रस्तुत किया था। लागत के रूप में काम एक लाख रुपये से अधिक का था और टेंडर एकान्त था, लेफ्टिनेंट। राज्यपाल ने इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया और उद्योग और श्रम विभाग (जिसे इसके बाद आईएलडी कहा जाएगा) के सचिव द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि उक्त मंजूरी की प्रत्याशा में काम तुरंत शुरू किया जाए। फिर भी ए-1 ने काम ए-2 को सौंपा, जिसने 15 मार्च 1966 को इसे क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। भारत सरकार से निविदा की कोई मंजूरी नहीं मिली, जिसने हालांकि निर्देश दिया कि काम विभागीय रूप से किया जाए।

दिनांक 16 मई, 1966 (प्रदर्श पी-7) के एक पत्र के माध्यम से, उक्त सचिव ने ए-1 को सूचित किया कि चूंकि कार्य को विभागीय रूप से निष्पादित किया जाना था, इसलिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के नियम 133 और 141 में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया था। पूरा करने के लिए और उसे एक बिल में उल्लिखित विभिन्न दरों के लिए

लोक निर्माण विभाग (संक्षेप में पीडब्ल्यूडी) की सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया, जिसे ए-1 ने काम के संबंध में भुगतान के लिए पहले प्रस्तुत किया था। रुपये की दर से दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिए ए-1 द्वारा 26 मई, 1966 को ऐसी सहमति प्राप्त की गई थी। 4.50 और रु. पुरुष और महिला मजदूरों के लिए क्रमशः 3.00 प्रति व्यक्ति, हालांकि प्रचलित पीडब्ल्यूडी दरें रु। 3.50 और रु. क्रमशः 2.00 (प्रदर्शन पी-9) दोनों अपीलकर्ताओं ने कार्य के निष्पादन के संबंध में सरकार को धोखा देने की साजिश रची। ए-2 कभी-कभी ए-1 को प्रत्येक दिन किए गए काम का हस्तलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें खुदाई की गई मिट्टी और नमक की घन मीटर में मात्रा, नियोजित पुरुष और महिला मजदूरों की संख्या (नाम के बिना) का विवरण निर्दिष्ट होगा, अनुमोदित दरों के अनुसार श्रम की लागत, नियोजित देशी शिल्प के लिए शुल्क, आदि। इनमें से किसी भी विवरण पर A-2 के हस्ताक्षर नहीं हैं। ए-1 अपने कार्यालय में इन विवरणों की टाइप की गई प्रतियां तैयार करवाएगा और ऐसी प्रतियों में से एक को अपने हस्ताक्षर के तहत मंजूरी के लिए आईएलडी को भेजेगा जो वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के बाद प्रदान की जाती थी। इसके बाद A-1 के कार्यालय में एक आकस्मिक बिल तैयार किया जाएगा और उस बिल में A-1 अपने हस्ताक्षर के तहत प्रमाणित करेगा कि कार्य GFR के नियम 141 के अनुपालन में विभागीय रूप से किया गया था, ऐसे प्रत्येक बिल के

साथ संबंधित ए-1 द्वारा हस्ताक्षरित कार्य विवरण की प्रति लेखा विभाग को भेजी जाएगी जो ए-1 के पक्ष में एक चेक जारी करेगा जो चेक की राशि वसूल करेगा और नियमित रसीद के आधार पर ए-2 को नकद भुगतान करेगा।

एक स्थिति ऐसी आ गई जब लेखा निदेशालय ने बिलों के भुगतान पर आपत्ति जताई और कार्य के निष्पादन के लिए नियोजित मजदूरों के मस्टर रोल मांगे। ए-1 ने तब एक कॉपी बुक (प्रदर्शनी पी-47) में प्रविष्टियों के आधार पर रजिस्टर प्रदर्शनी पी-37 और मस्टर रोल प्रदर्शनी पी-36 तैयार की थी, जिसे ए-2 द्वारा ए-1 को आपूर्ति की गई थी। मस्टर रोल में प्रविष्टियाँ संदिग्ध पाए जाने पर मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया, जिसने पाया कि कुल राशि रु. सरकार द्वारा ए-1 को 4,73,537.50 रुपये का भुगतान किया गया और उसके द्वारा ए-2 को, किया गया कार्य रुपये से अधिक का नहीं था। 76,247.43. यह वह निष्कर्ष था जिसके कारण अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया।

3. अब हम ए-1 द्वारा अपनाए गए रक्षा रुख का सारांश देंगे। उनके पास बंदरगाहों के कप्तान के अलावा कई कार्यालय थे और इस तरह उन्हें कई तरह के कर्तव्य निभाने पड़ते थे, जबकि उनके पास रखे गए कर्मचारी किसी भी मानक के हिसाब से बेहद अपर्याप्त थे, यहाँ तक कि उनके पास एक लेखा अधिकारी भी नहीं था। चूंकि कुम्बरजुआ नहर को गहरा और

चौड़ा करने के काम पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, इसके कार्यान्वयन के लिए निविदाएं बुलाई गईं और ए-2 को एकमात्र निविदाकर्ता पाया गया। ए-1 को सचिव, आईएलडी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि निविदा को मंजूरी देने वाला आवश्यक आदेश जल्द ही आएगा और आदेशों की प्रत्याशा में कार्य का निष्पादन तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। सहायक समुद्री सर्वेक्षक, श्री डिसूजा (पीडब्लू.4) को व्यक्तिगत रूप से उस काम की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था जो 15 मार्च, 1966 को शुरू किया गया था। अप्रैल, 1966 के अंत तक, ए-1 को बताया गया था कि काम पूरा होना चाहिए ए-2 के माध्यम से नहीं, बल्कि श्रमिक लगाकर विभागीय तौर पर निष्पादित किया गया। हालाँकि परिस्थितियों में यह संभव नहीं था और काम पहले की तरह चलता रहा। श्री डिसूजा (पीडब्लू. 4) प्रतिदिन खुदाई में निकली सामग्री की मात्रा और प्रकार की जाँच करते थे और तदनुसार अपनी नोटबुक में प्रविष्टियाँ करते थे। जब वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा निदेशालय द्वारा बिलों को पारित करने पर इस आधार पर आपत्ति की गई कि मस्टर रोल बनाए नहीं रखा जा रहा था, ए-1 ने श्री डिसूजा (पीडब्लू 4) से पूछताछ की और पता चला कि ए-2 ने एक गिरोह-वार मस्टर रोल बनाए रखा था जिसके आधार पर ए-1 के आदेश के तहत श्री डिसूजा (पीडब्लू 4) द्वारा दस्तावेज तैयार किए गए थे और आईएलडी को प्रस्तुत किए गए थे। कार्य बिलों के अनुरूप निष्पादित किया

गया था। ए-1 द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया गया। किसी भी मामले में, ए-1 ने सद्भावना से काम किया और यदि कोई बिल तथ्यों के अनुरूप नहीं है तो इसका कारण यह होगा कि उसे ए-2 द्वारा धोखा दिया गया है।

4. बचाव में ए-2 द्वारा अपनाया गया रुख भी कमोबेश वही था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि बिल लगे हुए श्रम के आधार पर नहीं बल्कि किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर तैयार किए गए थे, जिसका उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया।

ए-1 में कोई भी श्रम लगाया गया, कि खुदाई की गई कुल सामग्री 35,516.70 घन मीटर थी, किसी भी मस्टर या एक्विटेंस रोल को रखने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि काम मजदूरों द्वारा टुकड़ा-दर के आधार पर निष्पादित किया गया था और औसत संख्या कार्य के निष्पादन के लिए प्रति दिन काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 700 थी।

5. मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य से विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पाया कि निम्नलिखित तथ्य सिद्ध हैं:

(ए) ए-1 के निर्देशों के तहत कार्य का निष्पादन ए-2 द्वारा बाद वाले द्वारा प्रस्तुत निविदा से पहले शुरू किया गया था, जिसे लेफ्टिनेंट द्वारा अग्रेषित किया गया था। राज्यपाल द्वारा भारत सरकार को अनुमोदन हेतु स्वीकृत कर लिया गया था।

(बी) दिनांक 16 मई, 1967 के एक पत्र (प्रदर्शन पी-7) के माध्यम से सचिव, आईएलडी ने ए-1 को जीएफआर के नियम 141 और 133 में निर्धारित शर्तों के अनुसार विभागीय रूप से कार्य निष्पादित करने का निर्देश दिया और कार्य पर लागू विभिन्न दरों पर लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त करें। ऐसी सहमति वास्तव में A-1 द्वारा प्राप्त की गई थी (अक्षर P-8 और P-9 को प्रदर्शित करते हैं)।

(सी) कार्य ए-2 द्वारा अपने स्वयं के श्रम से किया जा रहा था और मस्टर रोल पर कोई भी श्रमिक ए-1 द्वारा नियोजित नहीं किया गया था।

(डी) ए-2 ने कार्य या सारांश के विवरण तैयार किए, जिसे उसने ए-1 को प्रस्तुत किया, जो फिर उसकी टाइप की गई प्रतियों पर हस्ताक्षर करेगा और उसे आईएलडी को मंजूरी के लिए अग्रेषित करेगा। ऐसी मंजूरी प्राप्त होने पर ए-1 आकस्मिक बिल तैयार करेगा और प्रत्येक पर हस्ताक्षर करेगा। उनमें से एक प्रमाण पत्र के साथ कि कार्य संलग्न सारांश के अनुसार जीएफआर के नियम 141 के अनुसार विभागीय रूप से किया जा रहा था। फिर प्रत्येक बिल को सारांश के साथ लेखा विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा जिसने ए-1 को संबंधित चेक जारी किया था। चेक की राशि तब A-1 द्वारा वसूल की गई और एक रसीद के तहत A-2 को भुगतान कर दिया गया।

(ई) 15-3-1966 से 6-4-1967 तक की अवधि के लिए मस्टर रोल प्रदर्शनी पी-36 ए-1 के कार्यालय में और उनके निर्देशों के तहत काम पूरा होने के बाद और आधार पर तैयार की गई थी। प्रदर्शन पी-47 का जिसे ए-2 ने बनाए रखा था। रजिस्टर प्रदर्शनी पी-37 इसी तरह ए-2 द्वारा प्रस्तुत और नियोजित श्रमिकों के विवरण वाले लिखित बयानों के आधार पर तैयार किया गया था।

6. विद्वान विशेष न्यायाधीश अपने समक्ष प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से नीचे दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचे:-

(i) ए-2 को पूरी तरह से पता था कि उसकी निविदा सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी और ए-1 को विभागीय रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया था।

(ii) कार्य के निष्पादन में ए-2 द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि रुपये से अधिक नहीं थी। 32,287.75 जिसके एवज में उन्होंने ए-1 की सहायता से रुपये की राशि प्राप्त करने का प्रयास किया। सरकार से 4,73,537.50 रु.

(iii) किसी भी बिल को लेखा विभाग द्वारा भुगतान के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनमें से प्रत्येक के साथ ए-1 द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र के लिए कि कार्य जीएफआर के नियम 141 के तहत विभागीय रूप से किया जा रहा था।

7. उपरोक्त निष्कर्षों से विद्वान विशेष न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों अभियुक्तों ने कार्य के निष्पादन के मामले में बड़े हुए बिल पेश करके और वास्तव में खर्च की गई राशि से कहीं अधिक राशि प्राप्त करके सरकार को धोखा देने की साजिश रची थी। अंततः बिलों का समर्थन करने के लिए तैयार किए गए मस्टर रोल में झूठे दावे शामिल थे और जाली दस्तावेज थे, और ए-1 को पूरी तरह से पता था कि जीएफआर के नियम 141 के अनुसार विभागीय रूप से किए जा रहे कार्य के संबंध में प्रमाण पत्र प्रत्येक बिल के साथ जोड़ा गया था। झूठा था. यह उनकी संतुष्टि के लिए साबित हुआ कि मस्टर रोल प्रदर्शनी पी-36 और रजिस्टर प्रदर्शनी पी-37 झूठे बिलों का समर्थन करने के लिए ए-1 द्वारा बेईमानी से या धोखाधड़ी से तैयार किए गए थे और यह ए-2 की सहायता से किया गया था। विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा किये गये कार्य पर वास्तव में खर्च की गई राशि केवल रु. 32,287.75, उन्होंने माना कि सरकार को रुपये के अधिक भुगतान में धोखा दिया गया था। 4,41,249.75.

इन्हीं परिसरों में विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि पहले कहा गया है।

8. विद्वान न्यायिक आयुक्त ने कार्य के निष्पादन में वास्तव में खर्च की गई राशि से संबंधित तथ्य को छोड़कर विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्ष को बरकरार रखा, जो उनकी राय में,

रूपये था। 76,247.43 जैसा कि पुस्तकों की प्रविष्टियों से पता चला है, पी-79 से पी-82 प्रदर्शित हैं, जो ए-2 के घर की तलाशी के परिणामस्वरूप बरामद किए गए थे। विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि और उन्हें दी गई सजा की पुष्टि विद्वान न्यायिक आयुक्त द्वारा की गई।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया कि ए-2 द्वारा प्रस्तुत निविदा वास्तव में सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और उसी आधार पर पूरा कार्य निष्पादित किया गया था। इस तर्क के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है और इसलिए हमें इसे सीधे खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। प्रदर्शन पी-7 में ए-1 को स्पष्ट सूचना है कि कार्य विभागीय तौर पर किया जाना था और इसलिए उसे काम की विभिन्न मदों पर लागू दरों के लिए लोक निर्माण विभाग की सहमति लेनी चाहिए। इस स्थिति का सामना करते हुए ए-1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जीएफआर के नियम 141 के तहत भी विभागीय रूप से किए जाने वाले किसी भी कार्य को एक ठेकेदार को सौंपा जा सकता है और इस कथन में वह सही है। हालाँकि, इससे उनका मामला आगे नहीं बढ़ता क्योंकि ठेकेदार के रूप में काम करने वाले ए-2 के माध्यम से निष्पादित किए गए कार्य के किसी भी हिस्से के आधार पर कोई बिल नहीं निकाला गया था और न

ही किसी भुगतान के लिए कोई मंजूरी दी गई थी। दूसरी ओर उन बिलों में काम के लिए लगे मजदूरों की संख्या और दावा की गई राशि स्वीकृत दरों पर उनकी मजदूरी से संबंधित थी। वास्तव में किसी भी बिल में इस तथ्य का उल्लेख तक नहीं है कि कोई ठेकेदार कार्य निष्पादित कर रहा था या ए-2 तस्वीर में कहीं भी था। इसमें यह तथ्य भी जोड़ें कि A-2 ने A-1 या ILD या, उस मामले के लिए, लेखा निदेशालय को कोई हस्ताक्षरित बिल या विवरण प्रस्तुत नहीं किया। जहां तक एक ओर ए-1 और दूसरी ओर सरकारी विभागों के बीच पत्राचार का सवाल है, ए-2 का नाम और कार्य के निष्पादन के साथ उसका संबंध उसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट रहा, सिवाय उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा के। चिंतित था और वह निविदा, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सरकार के किसी भी विभाग या कार्यालय द्वारा इसकी स्वीकृति से कभी प्रभावी नहीं हुई। इसलिए दोनों अपीलकर्ताओं ने उस अवधि के दौरान बिना किसी अनिश्चित शर्तों के जो स्थिति अपनाई, वह यह थी कि इसे सीधे विभाग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, न कि किसी ठेकेदार के माध्यम से। इसलिए एक ठेकेदार के रूप में ए-2 के माध्यम से इसके निष्पादन पर आधारित किसी भी याचिका को निरस्त किया जाना चाहिए।

10. अपीलों के समर्थन में एक अधिक गंभीर तर्क यह दिया गया कि वास्तव में निष्पादित कार्य का मूल्य वास्तव में ए-2 को भुगतान की गई

राशि, यानी रुपये से कम नहीं दिखाया गया था। 4,73,537.50. नीचे दी गई दो अदालतों द्वारा निकाले गए विपरीत निष्कर्षों पर हमले में यह प्रस्तुत किया गया है कि वे वास्तव में सबूतों के बजाय केवल अनुमानों पर आधारित हैं। और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने पर, यह हमला हमें अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है, जैसा कि हम वर्तमान में दिखाएंगे।

11. रुपये की राशि. ए-1 को 4 बिलों के एवज में 4,73,537.50 रुपये प्राप्त हुए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

सीरियल संख्या	बिल पर एक्ज़िबिट चिह्न	बिल की राशि
1	पी-13	98,294.50
	पी-18	82,811.00
2	पी-24	84,847.00
	पी-28	2,07,585.00
3		
4		
	कुल	4,73,537.50

जैसा कि पहले ही कहा गया है, ऊपर उल्लिखित प्रत्येक बिल के साथ नियोजित मजदूरों की संख्या का विवरण देने वाला एक दस्तावेज था।

प्रत्येक मजदूर को देय मजदूरी का लिंग और दर जैसे अन्य विवरण भी दस्तावेज़ में दिखाई दिए, जिन्हें "सारांश" के रूप में वर्णित किया गया है। यह सभी हाथों से स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक बिल संबंधित "सारांश" के अनुरूप है, लेकिन प्रस्तुत या पारित होने पर, किसी भी वाउचर के साथ नहीं था। राज्य की ओर से पेश किया गया मामला यह है कि सारांश में झूठी प्रविष्टियाँ थीं, ताकि काम के निष्पादन के लिए वास्तव में नियोजित मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि हो और यह उस खाते पर था कि अपीलकर्ता राज्य से धन निकालने में सक्षम थे। काम के निष्पादन के लिए वास्तव में उनके द्वारा भुगतान किए गए भुगतान से कहीं अधिक खजाना। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं की ओर से दावा यह है कि यह इंगित करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि सारांश और बिलों में की गई कोई भी प्रविष्टि तथ्यों के अनुरूप नहीं थी।

12. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पीडब्लू के मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण किया। 1, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 19 और 20 और देखा गया कि उन सभी स्थलों पर काम करने वाले देशी शिल्प के चालक दल सहित मजदूरों की संख्या, जहां विचाराधीन अवधि के दौरान ड्रेजिंग का काम चल रहा था, अलग-अलग थी। उन गवाहों की संख्या 80 से लेकर 200 तक है। उन्होंने इस तथ्य पर भी गौर किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत दर्ज किए गए बयान में भी ए-1 ने यह रुख अपनाया था कि जब

भी वह नहर पर काम करता है तो उसे कितने मजदूर मिलते हैं। साइट का दौरा किया, 200 और 250 के बीच भिन्न-भिन्न। फिर वह मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि रुपये की मात्रा निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े। निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 32,287.75:

"अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 द्वारा प्रस्तुत रसीदों से यह पता चलता है कि A.2 द्वारा मजदूरों और देश को भुगतान की गई राशि शिल्प मालिकों का बकाया 32,287.75 रुपये है। ए.2 के वकील ने जांच अधिकारी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया कि ए.2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अलावा, अन्य रसीदें भी थीं जो जांच अधिकारी द्वारा संलग्न नहीं की गईं और प्रस्तुत की गईं अभियोजन पक्ष द्वारा। A.2 का एकमात्र तर्क यह प्रतीत होता है कि, उपरोक्त प्राप्तियों से साबित हुई राशियों के अलावा, मजदूरों को भुगतान की गई अन्य राशियाँ भी थीं जिनके लिए रसीदें एकत्र नहीं की गईं। उपरोक्त सभी अभियोजन गवाहों ने इस सुझाव का खंडन किया था A.2 कि, उन राशियों के अलावा, जिनके लिए उन्होंने रसीदें पास की हैं, उन्हें अन्य राशियाँ भी प्राप्त हुई थीं, जिनके लिए उन्होंने रसीदें पास नहीं की थीं। केवल

पीडब्लू 14 और पीडब्लू 16 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि उन राशियों के अलावा, जिनके लिए उन्होंने रसीदें पास नहीं की थीं। उन्होंने रसीदें जारी की थीं, उन्हें कुछ कार्यों के लिए वेतन के आधार पर भुगतान भी किया गया था जिसके लिए उन्हें रसीदें जारी नहीं की गई थीं। हालाँकि, मेरे अनुसार, ये राशियाँ हजारों रुपये तक नहीं जा सकतीं। किसी भी तरह, यह साबित करना A.2 का काम था कि उसने अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई राशि के अलावा भी रकम खर्च की थी, जिसे करने में A.2 विफल रहा था।"

अब किसी आपराधिक आरोप के संबंध में सबूत की आवश्यकताओं के प्रति यह शायद ही कोई उचित दृष्टिकोण है। आरोप के प्रत्येक घटक के अस्तित्व को साबित करने का दायित्व हमेशा अभियोजन पक्ष पर रहता है और कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है। इसलिए, सभी उचित संदेहों से परे, यह सामने लाना राज्य का कर्तव्य था कि काम को पूरा करने में वास्तव में नियोजित मजदूरों की संख्या सरकार द्वारा भुगतान किए गए बिलों के साथ संलग्न सारांश में बताई गई संख्या से कम थी। यह सच है कि एक दिन में काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा 200 या उससे कम बताई गई है, जबकि बिलों में संलग्न

सारांश के अनुसार यह औसतन 370 से 756 तक थी। समय-समय पर नियोजित मजदूरों की वास्तविक संख्या के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों की धारणा पर भरोसा करना सुरक्षित है, जिन्होंने कार्य निष्पादित होने के काफी समय बाद गवाही दी थी? उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए और इस उत्तर का औचित्य गवाह से गवाह तक नियोजित श्रम की संख्या में भिन्नता द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान विशेष न्यायाधीश का दिमाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किए गए कार्य का मूल्य रुपये से अधिक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 32,287.75 कार्य के निष्पादन में अपीलकर्ताओं द्वारा की गई घोर अनियमितताओं से प्रभावित है, विशेष रूप से सभी भुगतानों से संबंधित वाउचर और उचित मस्टर रोल तैयार करने में उनकी विफलता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये अनियमितताएं कार्य के निष्पादन के मामले में अपीलकर्ताओं की प्रामाणिकता के संबंध में एक मजबूत संदेह को जन्म देती हैं, लेकिन संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, सबूत का विकल्प नहीं हो सकता। और आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर बेगुनाही साबित करने का बोझ डालना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है-

एक आपराधिक आरोप का संस्करण. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष न्यायाधीश ने ठीक यही किया है, यह देखते हुए कि "यह साबित

करना ए.2 का काम था कि उसने अभियोजन द्वारा साबित की गई राशि के अलावा भी राशि खर्च की थी, जिसे करने में ए.2 विफल रहा था।"

13. इस बिंदु पर विद्वान न्यायिक आयुक्त का निष्कर्ष एक समान दोष से ग्रस्त है। इसके संबंध में मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा:

"इन गवाहों के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि प्रतिदिन नहर में काम करने वाले मजदूरों की औसत कुल संख्या 100 से 160 थी। प्रति दिन औसतन 123 मजदूर लेते हैं, जिनमें से ए.2 द्वारा प्रस्तुत बयानों के आधार पर 12000 से कम पुरुष 4.50 रुपये की दर से और 13000 से कुछ अधिक महिलाएं 3.50 रुपये की दर से, हमारे पास श्रम पर लगभग 80,000/- रुपये की कुल राशि खर्च होती है। यह कमोबेश यही है वाउचर में उल्लिखित राशि के साथ। ए.2 की ओर से श्री एसवी नाइक ने इन गवाहों की जिरह में सुझाव दिया है कि प्रतिदिन नहर में काम करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या 350 से 400 थी। भले ही हम इस आंकड़े को स्वीकार कर लें। नियोजित श्रमिकों के खाते में देय कुल राशि 3,00,000.00 रुपये होगी, लेकिन आरोपियों ने 4,73,537.50 रुपये की राशि एकत्र की है।"

वास्तव में किए गए कार्य के मूल्य के मुद्दे पर उनका विद्वान विशेष न्यायाधीश से मतभेद था और इस संबंध में उन्होंने निर्णय के दूसरे भाग में इस प्रकार तर्क दिया है:

"आकस्मिक बिलों और उन्हें प्राप्त राशि के दावों के समर्थन में ए.1 या ए.2 द्वारा सरकार को कोई खाता बही या रसीदें प्रस्तुत नहीं की गईं। उनमें से किसी ने भी कोई खाता बही प्रस्तुत नहीं की या दिखाई नहीं दी। यह A.2 का मामला यह नहीं है कि उसे मजदूरों को किए गए भुगतान की रसीदें नहीं मिलीं, न ही उसका मामला यह है कि उसके पास काम के संबंध में कोई खाता-बही नहीं थी। वास्तव में, यह अविश्वसनीय होगा कि एक व्यवसायी या एक श्रम-आपूर्ति ठेकेदार को खाता बही नहीं रखनी चाहिए या किए गए भुगतान के लिए रसीदें प्राप्त नहीं करनी चाहिए। यह A.2 या A.1 का मामला नहीं है कि उन्होंने खाता बही या रसीदें खो दी हैं। जब एक खोज की गई तो ए.2 का निवास, रसीद किताबें एक्सएच. पी. 79 और पी. 82 और काम से संबंधित कुछ किताबें जब्त कर ली गईं। जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत ए. 2 से एक प्रश्न पूछा गया, तो इसके संबंध में यह साक्ष्य, उनका उत्तर

था कि न तो रसीद पुस्तकें और न ही पुस्तकें खाता पुस्तकें थीं। किताबों में रसीदें क्रम संख्या 101 से 700 तक हैं। पहली खोज में 14-4-66 से 25-1-68 तक की अवधि के लिए क्रम संख्या 151 से 200 वाली रसीदें गायब थीं। ये सभी रसीदें एक ही किताब में थीं, जिसका नाम था, एक्सह। पृ.82. पूर्व। बाद की तलाशी में पी.82 को जब्त कर लिया गया। एक अन्य पुस्तक पूर्व. बाद की खोज में पी.82 भी मिला। इस पुस्तक में कोई क्रमांक नहीं है। इन तीनों पुस्तकों में कार्य से संबंधित रसीदें शामिल हैं। कार्य से संबंधित रसीदों में अंकित कुल राशि रु. 76,248.43. A.2 ने यह नहीं बताया है कि उसके पास भुगतान किए गए किसी अन्य पैसे के लिए वाउचर थे और न ही उसने ऐसा कोई वाउचर प्रस्तुत किया है। पी.डब्ल्यू नंबर 7 से 10 और 14 से 21, कुल मिलाकर बारह, जिन्होंने नहर में खुदाई का काम किया था, ने कहा है कि उन्होंने उन्हें प्राप्त सभी धन की रसीदें दीं। जब उनमें से कुछ को सुझाव दिया गया कि उन्हें कुछ भुगतान बिना रसीद के किए गए थे, तो उन्होंने इस तथ्य से इनकार कर दिया। जब्त की गई अन्य पुस्तकें, अर्थात्, पूर्व। पी. 81 सामूहिक रूप से, ए.2 के अनुसार,

रोकड़ बहियाँ थीं। हालाँकि, क्रम संख्या 23/II आइटम संख्या 35, जो पूर्व का हिस्सा था। पी. 81 निश्चित रूप से एक खाता बही है न कि रोकड़ बही। किसी भी घटना में, A.2 इनमें से किसी भी पुस्तक पर भरोसा नहीं करता है और न ही उसने यह दिखाने के लिए कुछ कहा है कि उसमें कोई भुगतान दर्ज किया गया था, जो कि Ex में दिखाए गए भुगतानों के अलावा है। पी.79, 80 और 82. ए.2 ने नहर में काम करने वाले किसी भी श्रमिक की जांच नहीं की और उनके अनुसार, जिन्होंने कोई भुगतान प्राप्त किया था, जिसके लिए रसीद नहीं दी गई थी। Ex.P.79 से P.82 तक यह साक्ष्य है कि कार्य में व्यय किये गये कुछ धन की प्राप्ति हुई तथा उसका हिसाब-किताब किया गया। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस सवाल को खारिज किया जा सकता है कि ए.2 ने बिना रसीद प्राप्त किए किसी भी राशि का भुगतान किया होगा। पूर्व। पी.79 से पी.82 रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों के साथ अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करते हैं कि आरोपी द्वारा किए गए काम की कुल राशि रुपये से अधिक नहीं थी। 76,248.43।"

हम तुरंत कह सकते हैं कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि ए.2 के परिसर से जब्त की गई किताबों में काम के निष्पादन के लिए नियोजित श्रमिकों को उसके द्वारा किए गए सभी भुगतानों के बारे में प्रविष्टियां थीं और यह एक तथ्य है। जिसकी सत्यता हमें मानने का कोई कारण नजर नहीं आता। नीचे दी गई दो अदालतों द्वारा बनाई गई प्रकार की धारणाओं के खतरे को उन आंकड़ों में असमानता से उजागर किया गया है जो वे ऊपर उल्लिखित मूल्य की मात्रा के संबंध में पहुंचे थे। प्रत्येक का इसे देखने का अपना तरीका था; लेकिन फिर वे जिस गंभीर गलती में फंस गए, वह यह थी कि उन्होंने सोचा कि यह आरोपियों का काम है कि वे यह दिखाएं कि नियोजित मजदूरों की संख्या बिलों से जुड़े सारांश में प्रत्येक दिन के लिए दिखाई गई संख्या के अनुरूप है। और यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे कानून द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

14. विचाराधीन निष्कर्ष पर पहुंचने में विद्वान न्यायिक आयुक्त ने लासली रूपोर्ट डोनाॅड (पीडब्लू-6) के बयान पर भी विचार किया, जिन्होंने सितंबर, 1965 में और फिर मई, 1969 में नहर का सर्वेक्षण किया था, यानी पहले और बाद में दोनों। कार्य निष्पादित किया गया था और उस संबंध में दो दस्तावेज़ तैयार किए गए थे, अर्थात्, प्रदर्शन पी-55 और पी-66, जिसमें क्रमशः दो अवसरों पर उनकी टिप्पणियों का विवरण दिया गया

था। गवाह के अनुसार "डेटम से 10 फीट की गहराई तक खोदे जाने वाले ठोस पदार्थों की मात्रा 5858 घन मीटर के बराबर होती है"। यह आंकड़ा लगभग 28,324.70 क्यूबिक मीटर का पांचवां हिस्सा है, जो अपीलकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर काम के निष्पादन के दौरान हटाई गई और भुगतान की गई कुल सामग्री की मात्रा है। राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों आंकड़ों में असमानता ही दर्शाती है कि अपीलकर्ताओं का दावा झूठा है, हालांकि यह देखने में आकर्षक है, लेकिन गहराई से विचार करने पर यह हमें स्वीकार्य नहीं है। पीडब्लू-6 के अनुसार, दोनों अवसरों पर ली गई ध्वनियाँ लगभग समान थीं, जिससे यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई कि व्यावहारिक रूप से कोई काम नहीं किया गया था, जो कि किसी भी पक्ष का मामला नहीं है। इससे पता चलता है कि या तो दोनों दस्तावेजों की सामग्री उन टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करती है जो तथ्यों के अनुरूप नहीं थीं या जिन्हें, किसी भी मामले में, किए गए कार्य के निष्पादन के दौरान नियोजित श्रमिकों की वास्तविक संख्या की गणना के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शिका के रूप में नहीं लिया जा सकता था। दो सर्वेक्षणों के बीच से बाहर। इसके अलावा, राज्य के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान ऐसे किसी साक्ष्य की ओर आकर्षित नहीं किया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि नहर के वे हिस्से जहां पीडब्लू-6 द्वारा आवाजें ली गई थीं, उनकी चौड़ाई के संबंध में नहर की पूरी लंबाई का

प्रतिनिधित्व करते हैं और गहराई। फिर, गाद निकालने की प्रक्रिया, जो निरंतर चलती रहती है, को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। 1965 में जब पीडब्लू-6 द्वारा पहला सर्वेक्षण किया गया था और उस अवधि के अंत के बीच, जिसके दौरान काम निष्पादित किया गया था, बहुत सारी गाद नहर के तल पर जमा हो गई होगी और बाहर निकल गई होगी जो निश्चित रूप से होगी इसका मतलब है कि उनके अनुमान के परिणामस्वरूप 5858 घन मीटर के आंकड़े पर वास्तव में किए गए काम में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा गाद जमा हो सकती है और, जैसा कि कोई जानता है, काफी हद तक, काम के पूरा होने और उस समय के बीच जब पीडब्लू-6 ने 1969 में आवाज़ उठाई थी। ज्वार की स्थिति के लिए भी भत्ता देना होगा जब सर्वेक्षण किया गया. जैसा कि स्वयं गवाह ने बताया, 1969 की ध्वनियाँ निम्नतम ज्वार पर नहीं ली गई थीं। वैसे भी, गवाह को निम्नलिखित स्वीकारोक्ति करनी पड़ी जब उससे पूछा गया कि क्या वह अपने दो सर्वेक्षणों के आधार पर बता सकता है कि क्या बीच में कोई ड्रेजिंग की गई थी:

"यदि नहर में वर्ष 66 और 67 के दौरान कुछ ड्रेजिंग की गई है और 1969 में साउंडिंग ली गई है, तो यह लगभग 1965 की साउंडिंग के समान है, मैं यह नहीं कह पाऊंगा कि नहर में ड्रेजिंग की गई थी या नहीं...."

हम इसे बहुत असुरक्षित मानते हैं, सबूतों की इस स्थिति में विद्वान न्यायिक आयुक्त से सहमत होना कि पीडब्लू-6 द्वारा निकाले गए अनुमान और निकाली गई सामग्री की मात्रा के बीच असमानता यह साबित करती है कि "जिन दस्तावेजों पर पैसा लगाया गया था आरोपियों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े झूठे हैं।" हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, वह उन कारकों से भी प्रभावित थे जिन्होंने अपीलकर्ताओं के खिलाफ मजबूत संदेह पैदा किया।

15. राज्य के लिए विद्वान वकील उन साक्ष्यों का समर्थन करें जिनकी चर्चा हमने विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के साथ की है और पैराग्राफ 5 में आइटम (ए) से (ई) और आइटम (i) और (iii) के रूप में विस्तृत हैं। इस फैसले का पैराग्राफ 6. उन निष्कर्षों को विद्वान न्यायिक आयुक्त द्वारा तैयार किया गया था और हमारी स्पष्ट राय है, जिन कारणों से यहां दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, वे सही ढंग से निकाले गए थे। लेकिन उन निष्कर्षों से केवल यह पता चलता है कि अपीलकर्ताओं ने जीएफआर के प्रासंगिक नियमों और यहां तक कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों के निष्पादन के मामले में सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के प्रक्रियात्मक व्यवहार के सामान्य मानदंडों की घोर अवहेलना करते हुए काम को अंजाम दिया। हालांकि, इस तरह की उपेक्षा हमें किसी भी अपराध के बराबर नहीं दिखाई गई है जिसके

लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त निष्कर्ष उस संदेह को और भी मजबूत बनाते हैं जिसके बारे में हमने ऊपर बताया है, लेकिन मामला यहीं तक सीमित है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप के किसी भी तत्व को गलत ठहराया गया है।

इस पैराग्राफ में पहले उल्लिखित निष्कर्षों और साक्ष्यों के अलावा, राज्य की ओर से कोई भी सामग्री हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि विचाराधीन बिल या सारांश किसी भी विशेष रूप से झूठे थे।

16. हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के निष्पादन के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा या उनके कहने पर तैयार किए गए कई दस्तावेज़ तब अस्तित्व में नहीं आए जब कार्य प्रगति पर था, बल्कि बाद में जब उनके लिए मांग की गई। लेखा विभाग द्वारा किए गए, आरोप को इसके किसी भी प्रमुख के संबंध में बरकरार नहीं रखा जा सकता है, उन दस्तावेज़ों में की गई किसी भी प्रविष्टि के गलत होने का कोई सबूत नहीं है। परिणामस्वरूप, इसलिए, हम दोनों अपीलों को स्वीकार करते हैं, प्रत्येक अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि और लगाए गए वाक्यों को रद्द करते हैं और उन्हें संपूर्ण आरोप से बरी करते हैं।

एनवीके

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **रविन्द्र कुमार** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।
